KAPOT PUBLICATIONS

हिंदुओं से धोखा और भारत से द्रोह!

मोदी सरकार - 14 से 24 तक।



संदीप देव

हिंदुओं से धोखा
और
भारत से द्रोह!

मोदी सरकार - 14 से 24 तक।

संदीप देव

ISBN:

मोदी सरकार - 14 से 24 तक! हिन्दुओं से धोखा - भारत से द्रोह !

अनुसूची

1. मुस्लिम तुष्टिकरण में टूटा 67 साल का रिकॉर्ड

- ✓ 2014 से पहले और 2014 के बाद अल्पसंख्यक नीतियों का एक तुलनात्मक ब्यौरा
- ✓ अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर 50 हजार करोड़ से अधिक खर्च
- ✓ अल्पसंख्यकों के लिए 300 के करीब योजनाएं चला रही मोदी सरकार
- ✓ सरकारी योजनाओं में मुस्लिमों की भागीदारी
- ✓ नई हज पॉलिसी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किया बाईपास
- ✓ सच्चर कमेटी पर मोदी सरकार ने हिंदुओं को दिया बड़ा धोखा! सोनिया गांधी के सांप्रदायिक विधेयक का प्रावधान भी लागू
- ✓ वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
- ✓ मुस्लिम-ईसाइयों को एससी/एसटी कोटे में आरक्षण का लाभ देने की तैयारी
- ✓ रोहिंग्या/बंग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की योजना
- ✓ कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार से मोदी सरकार ने किया किनारा
- ✓ भाजपा शासित कुछ राज्यों का अल्पसंख्यक तुष्टिकरण भी देख लीजिए
- ✓ मुस्लिमों तुष्टिकरण से खुश अरब देशों ने किया पीएम मोदी को सम्मानित?

2. मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को बनाया संस्थागत

- ✓ इलेक्टोरल बांडः चुनावी चंदा या अवैध धंधा
- ✓ इलेक्टोरल बांड के जरिए मनी लाउंड्रिंग का खेल
- ✓ भारतीय राजनीति में घुसा विदेशी पैसा
- ✓ चंदा दो, धंधा लो
- ✓ चंदे की आड़ में चलाया अवैध वसूली रैकेट
- ✓ चंदा दो, नकली दवा का व्यापार करो
- ✓ चंदा दो और अपने लिए कानून बनवाओ
- ✓ ईडी/सीबीआई जांच एजेंसी नहीं, एक डरावना हथियार
- ✓ पीएम केयर फंड में क्या छुपा रहे हैं प्रधानमंत्री?
- ✓ सीएजी ने खोली मोदी सरकार के कई भ्रष्टाचारों की पोल
- ✓ ईवीएम मशीन कंपनी में भाजपा नेताओं बनाया निदेशक

3. कांग्रेसी भ्रष्टाचार और वंशवाद को आयात करती भाजपा

- ✓ कांग्रेसियों का हर भ्रष्टाचार, साफ करती मोदी सरकार
- ✓ भाजपा की वाशिंग मशीन और मोदी डिटर्जेंट पावउर में धुले नेताओं की असलियत।

4. गोरी, गजनी और औरंगजेब से भी बड़ा मंदिर-मूर्ति विध्वंशक

- ✓ हिंदू कोई धर्म नहीं है
- ✓ हिंदू देवी-देवताओं को छोड़ो
- ✓ हिंदू धर्मग्रंथों में करो बदलाव
- ✓ हर जगह शिवलिंग क्यों ढूंढ़ना?
- ✓ मंदिर-मूर्तियों में अतुल्य भारत है क्या?
- ✓ काशी विध्वंश में तोड़े पैराणिक मंदिरों की सूची
- ✓ काशी विध्वंश में तोड़े ऐतिहासिक मंदिरों की सूची
- ✓ अयोध्यास में तोड़े गये मंदिरों की सूची
- ✓ कर्नाटक में तोड़ डाले 2600 मंदिर
- ✓ संपूर्ण भारत में तोड़े गये मंदिर व मूर्तियों की सूची

5. राममंदिर और रामसेतु का झूठ और सच

- ✓ राम मंदिर को रोकने के लिए सरकार की आखिरी साजिश
- ✓ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की असली वजह बने हिंदू पुराण
- ✓ राम मंदिर केस में किसकी कितनी भूमिका?
- ✓ रामसेतु को तोड़ने का इतिहासः कौन, कब दोषी?
- ✓ रामसेतु के अस्तित्व से सरकार ने किया इनकार
- ✓ रामसेतु को धरोधर घोषित करने में आनाकानी

6. गोवंश के विनाश में वृद्धि, भारत बना दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश

- ✓ पिंक रिवोल्यूशन रोकने आए थे, पिंक रिवोल्यूशन बढ़ा दिया
- ✓ बीफ निर्यात में भारत बना दूसरा सबसे बड़ा देश
- ✓ गोवंश के मांस को पहली बार बनाया कानूनी
- ✓ गोवंश की तस्करी बैन, फिर भी धड़ल्ले से बिक रहा गो मांस
- ✓ गोरक्षकों के नेटवर्क को किया ध्वस्त
- ✓ शंकराचार्य जी का गोमाता-राष्ट्र माता अभियान

7. जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद-370 को पिछले दरवाजे से किया बहाल

- ✓ जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट और एग्रिकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट की फांस
- ✓ जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से मोदी सरकार का इनकार
- ✓ जम्मू-कश्मीर के मुस्लिमों को आरक्षण देने का कानून
- ✓ कश्मीर घाटी में हिन्दुओं को नहीं बसा पाई सरकार
- ✓ फिर हुआ हिंदुओं का पलायन
- ✓ जम्मू-कश्मीर में पहली बार शुरु हुई हिंदुओं की टारगेट कीलिंग
- ✓ कश्मीर घाटी में अरबी निवेश और संस्कृति का खोला रास्ता
- ✓ जम्मू को कश्मीर बनाने की तैयारी
- ✓ रौशनी एक्ट का खात्मा और सरकार की नाकमी
- ✓ घाटी में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से सरकार का इनकार
- ✓ लद्दाख भी सुलग उठा

8. विदेश नीति की विफलता और चीन का भारतीय जमीन पर कब्जा

- ✓ नेहरू के बाद मोदी काल में सबसे अधिक जमीन पर चीन का कब्जा
- ✓ नेपाल और बांग्लादेश ने भी किया भारत से जमीन हासिल
- ✓ भूटान ने चीन से मिलाया हाथ
- ✓ म्यांनमार करवा रहा पूर्वोत्तर में घुसपैठ
- ✓ श्रीलंका में चीन की मौजूदगी
- ✓ मालदीव से भारतीय सेना बाहर
- ✓ रूस ने पाकिस्तान को हथियार बेचना किया आरंभ
- ✓ अरब देशों ने रौंदी भारत की संप्रभुता
- ✓ ईरान से टूटा संबंध
- ✓ फिलिस्तीन में वही नेहरूवादी नीति
- ✓ अफगानिस्तान में तालिबान के सहारे

9. अमेरिकी हित सर्वोपरी

- ✓ करोना काल में अमेरिकी बिल गेट्स के हितों का संरक्षण
- ✓ अमेरिकी हित में छोटी बच्चियों पर लगाया निशाना
- ✓ अमेरिकी स्पॉन्सर्ड नई शिक्षा नीति
- ✓ एसीवाईपीएल में प्रशिक्षण और जनता की आंखों में धूल

10. गरीब हो रहे और गरीब, अमीर हो रहे हैं और अमीर

- ✓ देश पर बढ़ता विदेशी कर्ज
- ✓ अमीरों के माफ होते बैंक ऋण
- ✓ कारपोरेट टैक्स में छूट, मध्यवर्ग से लगातार लूट
- ✓ बढ़ती महंगाई और लुढ़कता भारतीय रुपया
- ✓ जीएसटी की मार, व्यापारी लाचार
- ✓ लघु उद्यमियों को समाप्त करने की तैयारी
- ✓ वोट खरीदने के लिए 80 करोड़ लोगों को बनाया भिखारी
- ✓ सुरसा की तरह बढ़ती बेरोजगारी
- ✓ अमीरों की चांदी, गरीबों का निकला दिवाला

11. दंगों में झुलसा भारत और सस्ती हिंदुओं की जान

- ✓ महीनों जलता रहा मणिपुर, प्रधानमंत्री बजाते रहे बांसुरी
- ✓ बंगाल से हिंदुओं का हुआ सबसे बड़ा पलायन
- ✓ 1984 के बाद पहली बार दिल्ली में हुए दंगे
- ✓ देश भर में 3500 से अधिक हिंदु विरोधी दंगे
- ✓ हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा पर जगह-जगह पथराव
- ✓ सीरिया स्टाइल में पहली बार देश भर में काटे गये हिंदुओं के गले
- ✓ आतंकवाद से अधिक वुल्फ अटैक में मारे गये हिंदू

2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। मोदी ने चुनाव के समय हिंदूओं से ढेर सारे वायदे किए थे, लेकिन आज सत्ता में 10 साल होने के उपरांत भी उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। यही नहीं, मुस्लिम तुष्टिकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार में मोदी सरकार ने कांग्रेस का पुराना रिकार्ड भी ध्वस्त कर दिया है। आज भारत की विदेश नीति ऐसी लचर है कि हमारे सभी पड़ोसी देशों में चीन का विस्तार हो चुका है और चीन हमारी करीब 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन को भी हड़प चुका है। महंगाई और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है।

ऐसे में वो राष्ट्रभक्त हिन्दू समाज जिसने कभी मोदी के लिए कैंपेन किया था और उनके प्रधान मंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया था, आज मोदी सरकार के विरुद्ध प्वाइंट वाइज एक चार्जशीट लेकर आया है। सनातनी जनता इसे स्वयं देखे और तय करे कि मोदी सरकार ने उन्हें क्या दिया है?

अध्याय 1

मुस्लिम तुष्टिकरण में टूटा 67 साल का रिकॉर्ड !



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हैं, लेकिन पिछले 10 साल की उनकी नीतियों को यदि देखें तो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक मुस्लिम तुष्टिकरण का रिकॉर्ड यदि किसी एक सरकार के नाम है तो वह यह मोदी सरकार ही है। उन्होंने तो बाकायदा मुस्लिम तुष्टिकरण को तृप्तीकरण और संतुष्टिकरण जैसा नाम देकर इसे औपचारिक बना दिया है।

2013 में नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरात सरकार के माध्यम से सोनिया गांधी की मनमोहन सरकार द्वारा 2006 में मुस्लिमों के लिए बनाई गयी सच्चर कमेटी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कि मजहब के आधार पर किसी समिति का गठन करना असंवैधानिक है। लेकिन 2014 प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने (मोदी ने) उसी सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को न केवल जोरशोर से लागू कर दिया, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कहे शब्द - "**संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है**", उसे योजनागत रूप से लागू कर दिया।

2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने का ब्यौरा संसद के पटल पर रखा था। आज केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओं में 70-77 फीसदी लाभार्थी केवल मुस्लिम हैं। आइए इससे संबंधित आंकड़ों पर

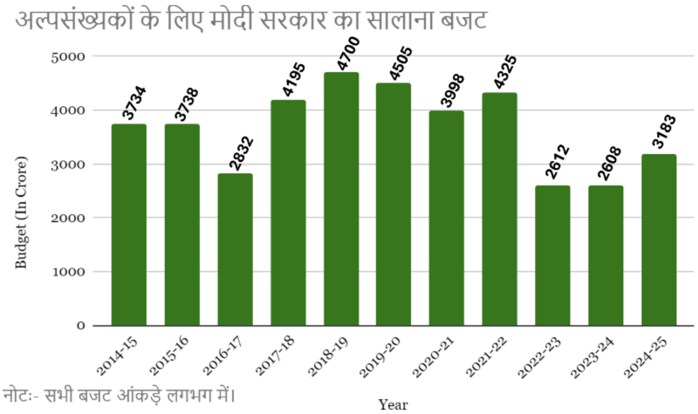
गौर करते हैं।

1.1) 2014 से पहले और 2014 के बाद अल्पसंख्यक नीतियों का एक तुलनात्मक ब्यौरा!

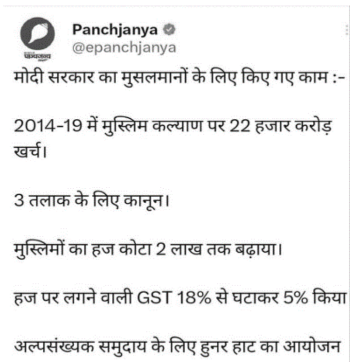
अल्पसंख्यक नीतियां	2014 से पहले	2014 के बाद
सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी	4.5 %	10 %
सिविल सर्विस में हिस्सेदारी	2.5 %	5 %
कौशल विकास प्रशिक्षण	20,000 लाभार्थी	21,50,000 लाभार्थी
छात्रवृत्ति	3.03 करोड़ को	5.20 करोड़ को
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	855 करोड़	1425 करोड़
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	493 करोड़	515 करोड़
एम.फिल / पीएचडी के लिए मौलाना **आजाद नेशनल फैलोशिप**	11,336 लाभार्थी	15,120 लाभार्थी
यूपीएससी/एसएससी/पीएससी (IAS) परीक्षा के लिए **नई उड़ान योजना**	483 लाभार्थी	4142 लाभार्थी
विदेश में पढ़ने के लिए **पढ़ो परदेश योजन**	0	3251 लाभार्थी
अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए **बेगम हजरत महल योजना**	1,49,382 लाभार्थी	2,57,908 लाभार्थी
सीखो और कमाओ	20,164 लाभार्थी	3,17,290 लाभार्थी
उस्ताद योजना	0	19,704 लाभार्थी
नई मंजिल योजना	0	1,00,000 लाभार्थी
गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट योजना	0	1,06,600 लाभार्थी
नई रौशनी योजना	97,825 लाभार्थी	2,95,000 लाभार्थी
अल्पसंख्यक लड़कियों को छात्रवृत्ति	90.5 लाख लाभार्थी	121 लाख लाभार्थी
अल्पसंख्यक केंद्रित संरचना का निर्माण	22,477	18,875
हुनर हाट योजना	ऐसी योजना नहीं थी	2 लाख लाभार्थी
स्वरोजगार के लिए ऋण	1786 करोड़ रुपये	1979 करोड़ रुपये
वितरित ऋण की राशि	325.46 करोड़ रुपये (2013-14)	881.7 रुपये करोड़ (2022-23)
ऋण से लाभान्वितों की संख्या	75,966 (2013-14)	2,05,777 (2022-2023)
सरकारी संसाधनों पर अल्पसंख्यकों को अधिकार	करीब 15-25 फीसदी	करीब 30-40 फीसदी

1.2) अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर 50 हजार करोड़ से अधिक खर्च!

अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार ने विकास बजट की शुरुआत की। पूर्व की मनमोहन सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय को आवंटित बजट से मोदी सरकार का बजट कहीं अधिक रहा।

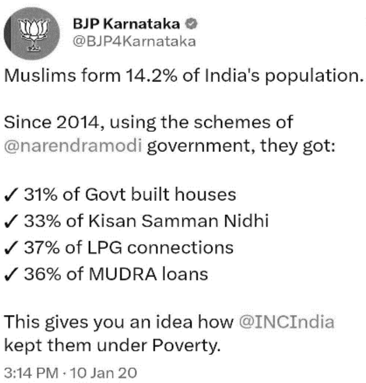


इसे यदि जोड़ कर देखें तो मोदी सरकार ने 2014-2024 के बीच अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर आम करदाताओं के करीब 40,430 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने इस पर गर्व जाहिर करते हुए लिखा कि 2014-2019 के बीच ही मोदी सरकार ने मुस्लिम कल्याण पर 22 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए।



अल्पसंख्यक मंत्रालय के अतिरिक्त कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय आदि की सरकारी योजनाओं जैसे **कौशल विकास योजना**, **प्रधानमंत्री आवास योजना**, **शौचालय योजना** या फिर **अलिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट में वृद्धि** आदि को जोड़ दें तो अल्पसंख्यक समाज पर किया गया यह खर्च 50,000 करोड़ से कहीं अधिक हो जाता है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक अल्पसंख्यक बजट है।

अल्पसंख्यक के नाम पर जारी इतने बड़े बजट का 70-80 फीसदी हिस्सा केवल



BJP Karnataka
@BJP4Karnataka

Muslims form 14.2% of India's population.

Since 2014, using the schemes of @narendramodi government, they got:

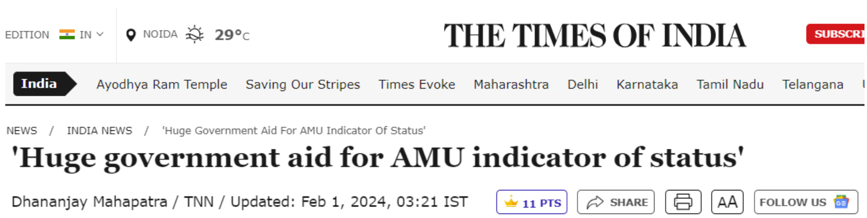
✓ 31% of Govt built houses
✓ 33% of Kisan Samman Nidhi
✓ 37% of LPG connections
✓ 36% of MUDRA loans

This gives you an idea how @INCIndia kept them under Poverty.

3:14 PM · 10 Jan 20

मुस्लिम समुदाय पर खर्च किया गया है। अर्थात् स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम तुष्टिकरण पर इतना बड़ा बजट आज तक किसी सरकार ने खर्च नहीं किया, जितना कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया है।

भारत विभाजन की नींब जिस **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय** से पड़ी और जहां आज भी जिन्ना की तस्वीर हटाने पर दंगे हो जाते हैं, वहां मोदी सरकार ने 'अल्पसंख्यकवाद' के नाम पर पानी की तरह आम करदाताओं का पैसा बहाया है। अलीगढ़ मुस्लिम विवि का बजट बढ़ाने में मोदी सरकार ने विशेष दिलचस्पी दिखाई है।



EDITION IN | NOIDA 29°C | THE TIMES OF INDIA | SUBSCRI

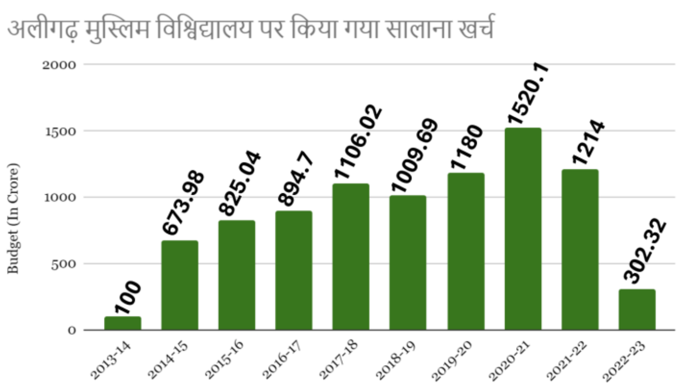
India | Ayodhya Ram Temple | Saving Our Stripes | Times Evoke | Maharashtra | Delhi | Karnataka | Tamil Nadu | Telangana

NEWS / INDIA NEWS / 'Huge Government Aid For AMU Indicator Of Status'

'Huge government aid for AMU indicator of status'

Dhananjay Mahapatra / TNN / Updated: Feb 1, 2024, 03:21 IST | 11 PTS | SHARE | AA | FOLLOW US

अर्थात् मोदी सरकार ने अपने नौ साल के कार्यकाल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय को करीब 9,000 करोड़ का फंड जारी किया है। इसी तरह **जामिया मिलिया इस्लामिया** को 2014-2023 के बीच करीब 3400 करोड़ रुपये जारी किया गया है।



भारत और पाकिस्तान दोनों के विभाजन के एक सबसे बड़े कारक उर्दू भाषा के विकास पर मोदी सरकार ने 2014-23 के बीच करीब 713 करोड़ रुपये खर्च किया है।



Hindustan Times | Get App

Home / Education / Funds for promotion of Urdu lan...

Funds for promotion of Urdu language almost doubled in five years: HRD

Hindustan Times, New Delhi | By HT Correspondent

Oct 02, 2019 09:28 AM IST

FOLLOW ON Google News

यदि अल्पसंख्यक मंत्रालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बजट का पैटर्न देखें तो पता चलता है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के बीच के वर्षों में इनके लिए खूब बजट जारी किया है, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए वह चुनावी साल के .

नजदीक बजट कम जारी करती है और इसका प्रचार करवा देती है, जिससे हिंदू खुश हो जाते हैं। यह प्रचार संसद के अंदर ओवैसी से लेकर मीडिया में बैठे सरकारी पत्रकार और सोशल मीडिया के मास्टरस्ट्रोकवादी इंफ्लूएंसर-एक साथ करते हैं और बिना पूरे बजट की जानकारी के हिंदू इस जाल में फंस जाते हैं।

केंद्र की अल्पसंख्यक कार्यक्रम पर खर्च किए गये 50,000 करोड़ के इस बजट में यदि सभी राज्यों के अल्पसंख्यक कार्यक्रम वाले बजट को भी जोड़ दें तो यह 1 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है।



NEWS18 | LIVE TV

Yogi Govt Allocates Rs 479 Crore for Madrasas in Biggest State Budget Till Date

Budget 2020-21 which is the fourth budget of the Yogi Adityanath led Bharatiya Janata Party government in the state, exceeds last year's budget by Rs 33,159 crore.



Newsum
@Newsumindia

Maharashtra increases govt guarantee to Maulana Azad Minorities Financial Development Corporation from Rs 30 crore to Rs 500 crore

newsum.media
Maharashtra increases govt guarantee to Maulana Azad Minorities Financial Development C...

1:33 pm · 30 Nov 23 · 10.4K Views

1.3) अल्पसंख्यकों के लिए 300 के करीब योजनाएं चला रही मोदी सरकार

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दिकी के अनुसार, केंद्र की भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 300 से अधिक योजनाएं

चलाई हैं, जिसमें सबसे अधिक लाभार्थी गरीब मुसलमान हैं। इन योजनाओं में कुछ प्रमुख योजनाएं हैंः



- ✓ नई रौशनी योजना,
- ✓ नई उड़ान योजना,
- ✓ उस्ताद योजना,
- ✓ नया सवेरा योजना,
- ✓ पढ़ो परदेस योजना,
- ✓ नई मंजिल योजना,
- ✓ प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति,
- ✓ पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति,
- ✓ मुफ्त हज यात्रा योजना
- ✓ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम,
- ✓ सीखो और कमाओ योजना, आदि

नया सवेरा मुफ्त कोचिंग योजना के तहत 1.19 लाख मुस्लिम विद्यार्थी लाभान्वित हुए। 2019-22 में अल्पसंख्यकों की नौकरी के लिए 19,907 सीटें आवंटित की गई।



अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग के लिए 'नई उड़ान' योजना लागू की गई। इसमें सिविल सर्विस, स्टाफ सलेक्शन कमीशन और राज्य सेवा अयोग में अल्पसंख्यों की बहाली के लिए अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार **मुफ्त आवासीय कोचिंग** उपलब्ध कराती है।



इसके तहत 2018 से 2023 तक 33.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गये। 5,194 अल्पसंख्यक छात्रों को इसमें लाभान्वित किया गया।

इस 'नयी उड़ान' योजना के तहत ही बड़ी संख्या में सिविल सर्विस अर्थात् आईएस/आईपीएस, स्टाफ सलेक्शन एवं राज्य सेवा अयोग की परीक्षा में मुस्लिमों को भर्ती किया जा रहा है।

इस योजना के कारण स्वतंत्रता के बाद से सिविल सेवा में सर्वाधिक मुसलमान मोदी सरकार के दौरान ही चुने गये।

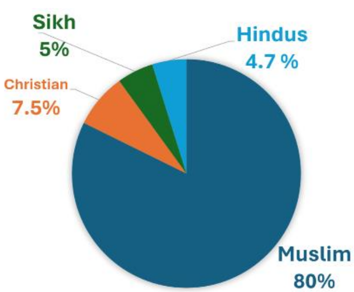
2016 में 52 और 2017 में 50 मुस्लिम छात्रों की भर्ती हुई, जो आजादी के बाद किसी वर्ष में सर्वाधिक मुसलमानों के चयन का रिकॉर्ड है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार मुस्लिमों के मुफ्त यूपीएससी कोचिंग पर पिछली सरकारों से अधिक खर्च कर रही है, क्योंकि वह अधिक से अधिक मुस्लिमों को IAS और IPS में भर्ती करना चाहती है।

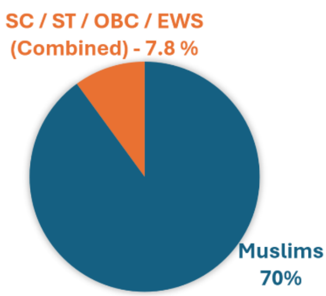
सिविल सर्विस के साक्षात्कार में मुस्लिम उम्मीदवारों को अतिरिक्त 13 नंबर दिए जाने का खुलासा 2020 में एक अध्ययन के उपरांत हुआ।

'नई उड़ान' योजना के लिए 2018-2023 तक सरकार ने 33.68 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिससे 5,194 छात्र लाभान्वित हुए।

केंद्र सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (जो भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रद्यौगिकी विभाग के अधीन आता है) पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार ने जितनी छात्रवृत्ति (स्कालरशिप) बाकि सब समुदायों को मिला कर दी उससे कई गुना अकेले मुस्लिम समुदाय को दी। इसके दो वर्षों (2018-19 तथा 2019-20) का डाटा नीचे दिया हुआ है :



SCHOLARSHIP (2018-19)



SCHOLARSHIP (2019-20)

इसी पोर्टल के अनुसार 7.15 लाख हिंदुओं को विभिन्न परीक्षाओं में कुल 571.78 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली, वहीं 65 लाख मुस्लिम छात्र-छात्राओं को कुल 1770 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

हिंदुओं से अधिक छात्रवृत्ति पाने वालों में अनुपात रूप से कम जनसंख्या वाले क्रिश्चिन समुदाय के छात्र भी शामिल रहे। 9.81 लाख क्रिश्चिन छात्रों को, जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कुल छात्र-छात्राओं के 10.6 फीसदी हैं, उन्हें 375.94 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 1425 करोड़ और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 515 करोड़ रुपये खर्च किए गये। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के दिए आंकड़ों के मुताबिक अल्पसंख्यकों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में यूपीए सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार ने 42.2 फीसदी की बढोत्तरी की है।

नई मंजिल योजना

मोदी सरकार ने 207 करोड़ रुपये खर्च कर, 99,980 अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया गया।

उस्ताद योजना

मुस्लिमों के हुनर को विदेश पहुंचाने के लिए 7393 मुस्लिमों को दिया प्रशिक्षण।

इसके लिए 167 करोड़ की राशि की आवंटित। प्रशिक्षण पाने वाले कुल अल्पसंख्यकों में से 77 फीसदी केवल मुसलमान हैं।

विरासत योजना

अल्पसंख्यक कारीगरों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप

एम.फिल/पीएचडी करने के लिए दो हजार अल्पसंख्यक छात्रों को 25.34 करोड़ रुपये की फेलोशिप स्टाइपेंड प्रदान किया गया।

सीखो और कमाओ योजना

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 690 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई और 1,87,565 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

स्वरोजगार योजना

अल्पसंख्यों को स्वरोजगार के लिए 20-30 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया।

सीखो और कमाओ योजना

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 690 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई और 1,87,565 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

नई रौशनी योजना

40,300 अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, जिस पर मोदी सरकार ने 18.50 करोड़ रुपये खर्च किये।

यही नहीं, **प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम** के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए

- ✓ 42 डिग्री कॉलेज,
- ✓ 180 आवासीय स्कूल,
- ✓ 3,062 स्कूल बिल्डिंग,
- ✓ 24 महिला छात्रावास,
- ✓ 81,503 पेयजल सुविधा और
- ✓ 9,330 शौचालय का निर्माण कराया गया।

मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी संख्या में बजट जारी किया गया। केवल छह सालों में मरदसा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये जारी किए गये।

Year (वर्ष)	Budget (बजट)
2016 to 2021	520 Crore
2022-23	160 Crore

मेडिकल की NEET परीक्षा में सितंबर 2022 में एकाएक 1200 मुस्लिम छात्र एक साथ निकले। ये सभी छात्र मदरसा में पढ़ रहे थे। इनमें कुछ छात्र हाफिज थे और कुरान सीख रहे थे। बाद में पता चला कि ये सभी ***तीन मुस्लिम कोचिंग संस्थान*** *से परीक्षा की तैयारी भी साथ-साथ कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में 70 शाखाओं के साथ फैली* ***अल-अमीन*** *से 500 छात्र,* ***अजमल फाउंडेशन कोचिंग*** *से 250 छात्र एवं* ***शाहीन समूह संस्थान*** *से 450 छात्र निकले थे। ये सभी कोचिंग संस्थान केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाते हुए मुस्लिम छात्रों को सिविल सर्विस से लेकर मेडिकल तक में नियुक्ति दिलवाने के लिए संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं।*

असम के मुस्लिम सांसद **बदरुद्दीन अजमल** द्वारा संचालित **अजमल फाउंडेशन को केंद्र सरकार से बड़ी संख्या में ग्रांट भी मिलता है**। 2017-2018 को 'नई मंजिल' योजना के क्रियान्वयन के लिए अजमल फाउंडेशन को 5,48,05,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इसी तरह बंगाल के अल-अमीन-मिशन ट्रस्ट को 2026-17 में एक करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई।

ऐसे ही जकात फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को सिविल सर्विस से लेकर अन्य सरकारी

नौकरियों में संगठित रूप से भर्ती करवा रहा है। 2019 में सिविल सर्विस में चयनित 42 मुस्लिमों में से 27 जमात फाउंडेशन से निकले थे। जमात फाउंडेशन को 'सच्चर कमेटी' में शामिल और अलीगढ़ मुस्लिम विवि से स्नातक एक पूर्व आईएएस सैय्यद जफर महमूद ने 2008 में बनाया था। जफर महमूद ने अक्टूबर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के आलोक में यह विभाजनकारी बयान दिया था कि, " *भारतीय मुसलमान तेजी से निराश हो रहे हैं।*" यही नहीं, उप्र के एटीएस द्वारा 150 करोड़ के धर्मांतरण रैकेट में पकड़े गये और अभी जमानत पर बाहर **मौलाना कलीम सिद्दिकी** जकात फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया शरिया काउंसिल के सदस्य रहे हैं! जकात के संस्थापक से लेकर इसके सदस्य तक की विचारधारा से देश की जनता समझ सकती है कि इस संस्थान से निकले नौकरशाहों की मानसिकता आगे चलकर किस विचारधारा को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी?

ऐसे ही कई मुस्लिम संगठन और संस्थाएं सीधे केंद्र सरकार से लाभान्वित हो कर सिविल सर्विस, सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संगठित रूप से मुस्लिमों के भर्ती अभियान को संचालित कर रही हैं।

अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना के तहत आम हिंदू करदाताओं के धन का बंदरबांट और घोटाला कैसे हो रहा है, इसका खुलासा अगस्त 2023 में हुआ। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश में मदरसों सहित 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में 830 संस्थान और 53 फीसदी छात्र फर्जी पाए गये। महज पांच साल में 144 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ में आया है। यदि पूरे 10 साल की जांच कराई जाए तो यह घोटाला काफी बड़ा निकलेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है।



INDIA TODAY

Magazine | Live TV | Search

News / India / Biggest minority scholarship scam busted, 53% of institutions 'fake'. CBI to pr...

Biggest minority scholarship scam busted, 53% of institutions 'fake'. CBI to probe

It has come to notice that 53% of institutions under a minority scholarship programme across several states are fake, leading to a Rs 144.83-crore scam over 5 years. Union Minister Smriti Irani has ordered a CBI inquiry into the issue.

Sources said that despite being non-existent or non-operational, the institutions managed to get registered on the National Scholarship Portal. (Photo: Reuters)

Gaurav C Sawant

New Delhi, UPDATED: Aug 19, 2023 19:54 IST

1.4) सरकारी योजनाओं में मुस्लिमों की भागीदारी

2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की जनसंख्या इस देश की कुल आबादी का 14.2 फीसदी है, लेकिन 2014 के बाद की सभी सरकारी योजनाओं में इनकी भागीदारी इनकी जनसंख्या से करीब तीन गुणा है। जैसे,

योजना का नाम	मुस्लिम लाभार्थी	टिप्पणी
प्रधानमंत्री आवास योजना	31%	2021-22 में 5,903 करोड़ की लागत से 44 लाख से अधिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास में घर दिया गया।
किसान सम्मान निधि योजना	33%	
पीएम उज्जवला योजना (LPG Gas Cylinder)	37%	
मुद्रा लोन योजना	36%	केवल आठ सालों में मोदी सरकार ने मुद्रा योजना में 23.2 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया। कुल 40.82 करोड़ लोगों को लोन दिया गया, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में लोन मुस्लिमों को मिला।

22 जुलाई 2023 को मोदी सरकार ने संसद के अंदर यह जानकारी दी कि देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ पहुंच चुकी है। 2014 के बाद 50 फीसदी मुसलमानों को हमारी सरकार की योजना के कारण पहली बार घर मिला है। 94.9 फीसदी मुस्लिमों के पास सरकार ने पानी का बेहतर स्रोत उपलब्ध कराया है और 97.2 फीसदी मुसलमानों तक शौचालय की सुविधा पहुंचाई है।

सरकार संसद में खुलकर अल्पसंख्यक की जगह मुस्लिम बोल कर उसके आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी, जिससे स्पष्ट है कि वह अपनी योजनाओं ने न केवल मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, बल्कि उसे मुस्लिमों तक पहुंचाने के लिए उसे जमकर प्रचारित भी कर रही है। **हां, चुनावी रैली में हिंदुओं को धोखा देने के लिए वह अवश्य दूसरी पार्टियों को 'तुष्टिकरणवादी' कहती रहती है, जबकि आजादी के बाद खुलकर और सबसे अधिक 'मुस्लिम तुष्टिकरण' यदि किसी सरकार ने किया है तो वह भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार है।**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अप्रैल 2022 को यह घोषित किया था कि '*भाजपा का लक्ष्य भारत को तुष्टिकरण से तृप्तिकरण की ओर ले जाना है।*' देखा जाए तो वह देश को उसी ओर ले जा रहे हैं!

1.5) नई हज पॉलिसी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किया बाईपास!

मोदी सरकार ने 2023 में एक नई 'हज पॉलिसी' लागू की। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि धीरे-धीरे हज सब्सिडी को समाप्त किया जाए। उस समय हज सब्सिडी पर कांग्रेस की यूपीए सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तोड़ निकालने के लिए 'विशेष छूट' का रास्ता अपनाते हुए मुस्लिम हज यात्रियों पर पहले से भी कई गुणा सरकारी खजाना लुटा दिया।

मोदी सरकार ने हज यात्रा के लिए **आवेदन शुल्क को माफ कर दिया** है। पहले हज यात्रा के आवेदन फार्म की कीमत जहां 350 रुपये थी, वहीं इसे मोदी सरकार ने निःशुल्क कर दिया है। यही नहीं, हर हज यात्री को **50,000 रुपये की 'विशेष छूट'** प्रदान की गई है। इसके तहत सूटकेस, चादर आदि के लिए सीमा शुल्क ही समाप्त कर दिया गया। साथ ही हज पर लगने वाले **जीएसटी को 18 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी** कर दिया है।

स्वतंत्रता के बाद पहली बार अधिकतम 1,75,000 मुसलमानों ने हज यात्रा किया।

इन छूटों का असर यह हुआ कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार अधिकतम 1,75,000 मुसलमानों ने हज यात्रा किया। यदि इन 1,75000 यात्रियों को मिले 50,000 रुपये की 'विशेष छूट' तथा मोदी सरकार द्वारा दिए गए निःशुल्क आवेदन फार्म की कीमत को जोड़ दिया जाए तो यह राशि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त कराए गये 200 करोड़ की सब्सिडी से कई गुणा अधिक (881 करोड़ से भी अधिक) हो जाती है।

$$175000 \times (50000 + 350) = 881 \text{ करोड़}$$

यात्रियों की संख्या | सरकार की विशेष छूट | निशुल्क आवेदन फार्म

अर्थात् मोदी सरकार ने हज पर 'विशेष छूट' देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाईपास करने का रास्ता भी ढूंढ लिया और अपने प्रिय मुस्लिम समुदाय को सरकारी खजाने से कांग्रेस सरकार से कई गुणा अधिक लाभ भी पहुंचा दिया।

बता दें कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सउदी अरब के सुल्तान से बात कर हज कोटा को 2 लाख तक करवाया था।



1.6) सच्चर कमेटी पर मोदी सरकार ने हिंदुओं को दिया बड़ा धोखा! सोनिया गांधी के सांप्रदायिक विधेयक का प्रावधान भी लागू!

सोनिया की मनमोहन सरकार द्वारा 2005 में मुस्लिमों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में 'सच्चर कमेटी' का गठन किया गया था। जस्टिस सच्चर ने एक साल बाद ही 2006 में 403 पेज की यह रिपोर्ट तत्कालीन केंद्र सरकार को सौंप दिया, जिसे 30 नवंबर 2006 को संसद में पेश किया गया। इसके तहत मुसलमानों के कल्याण पर 75 फीसदी खर्च केंद्र सरकार और 25 फीसदी खर्च राज्य सरकारें उठाती हैं। यह योजना प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तौर पर बनाई गई। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले 2008 में आनन-फानन में यूपीए सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा कर दी। इसके अलावा सोनिया गांधी की असंवैधानिक सत्ता नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (NAC) ने एक सांप्रदायिक बिल भी प्रस्तावित किया था, जो हिंदुओं के विरोध को देखते हुए लागू तो नहीं हुआ, लेकिन इसके कुछ प्रावधान सच्चर कमेटी में भी थे, खासकर मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम पुलिसकर्मियों की बहाली, जो दंगा आदि की स्थिति में अन्य समुदाय, खासकर हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक थे।

2008 में सच्चर कमेटी के लागू होने की घोषणा के बाद भी यूपीए की तत्कालीन केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारें उसे उतनी अच्छी तरह से लागू नहीं कर सकी, जितनी की गुजरात की मोदी सरकार ने किया। एक रिपोर्ट बताती है कि सच्चर

कमेटी का सबसे बढ़िया क्रियान्वयन गुजरात की मोदी सरकार ने किया था। उदाहरण के लिए 'टाइम्स ऑफ इंडिया' अखबार की 12 नवंबर 2012 की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि 'पुलिस स्टेशनों में सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम पुलिसकर्मियों की तैनाती वाले राज्य के रूप में गुजरात उभरा है, जिसने मुस्लिम समुदाय की उच्च जनसंख्या वाले राज्यों को भी पछाड़ दिया है।'


EDITION IN NOIDA 29°C THE TIMES OF INDIA

India Ayodhya Ram Temple Saving Our Stripes Times Evoke Maharashtra Delhi Karnataka Tamil N

Gujarat tops states in number of Muslim policemen

Vishwa Mohan / TNN / Updated: Nov 12, 2012, 01:41 IST

SHARE AA FOLLOW US

New For You

The data, shared by the home ministry in response to an RTI query filed by TOI, shows that 10.6% of cops posted in police stations across Gujarat are Muslims.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने एक आरटीआई डाला था, जिसके जबाव में यूपीए सरकार के गृहमंत्रालय ने यह आंकड़े उपलब्ध कराए थे। उन आंकड़ों से पता चला कि पुलिस स्टेशनों में तैनात गुजरात के 10.6 फीसदी पुलिसकर्मी मुस्लिम हैं। यह राज्य की 2001 की जनसंख्या में मुसलमानों के 9.1 फीसदी अनुपात से अधिक था।

बता दें कि 'सच्चर कमेटी' की एक सिफारिश यह भी थी कि 'मुस्लिम समुदाय के बीच विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस स्टेशनों में अधिक मुसलमान पुलिसकर्मियों की बहाली की जाए।' अन्य राज्य जहां इसे नहीं कर सके, वहीं नरेंद्र मोदी की तत्कालीन गुजरात सरकार ने अपने 501 पुलिस स्टेशनों में भर्ती 47,424 पुलिसकर्मी में से 5,021 पुलिसकर्मी मुस्लिम बहाल किए। यह प्रावधान सोनिया गांधी की 'एनएसी' द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा विधेयक में भी शामिल था, जिसे बेहतरीन ढंग से गुजरात की मोदी सरकार ने प्रदेश में लागू किया था और आज केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में भी लागू कर दिया है।

2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा था। केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार 'सच्चर कमेटी' का क्रियान्वयन उतनी ठीक से नहीं कर सकी थी, जितनी कि गुजरात की मोदी सरकार ने किया था। अतः आनन-फानन में चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले यूपीए सरकार ने मुस्लिम वोट पाने के लिए 21 फरवरी 2014 को एक प्रेस रिलीज जारी कर यह घोषणा की कि सच्चर समिति की रिपोर्ट में

सूचीबद्ध 76 सिफारिशों में से 72 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और इन 72 सिफारिशों में भी सिर्फ 43 के संबंध में फैसले लिए गये हैं और इन्हें क्रियान्वित कराने की जिम्मेवारी संबंधित मंत्रालयों को सौंपे गये हैं। पीआईबी द्वारा जारी यह सरकारी प्रेस रिलीज साफ-साफ बता रहा था कि 2008 से 2013 तक यूपीए सरकार ने 'सच्चर कमेटी' को ठंडे बस्ते में डाले रखा और जब आम चुनाव का समय आया तो मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए उसने सिफारिशों को स्वीकार करने की केवल घोषणा कर दी।

उधर 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं को भ्रमित करने और खुद को मुस्लिम विरोधी दर्शाने के लिए गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार 'सच्चर कमेटी' का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। जिस गुजरात सरकार ने हर क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से 'सच्चर कमेटी' के सुझावों को लागू किया था, उसके मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब हिंदुओं का वोट लेने के लिए कमेटी के विरोध का दिखावा करने सुप्रीम कोर्ट और मीडिया में पहुंचे चुके थे!


The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Gujarat to Supreme Court: Sachar panel illegal,only to help Muslims

Centre in its affidavit had defended the scheme.

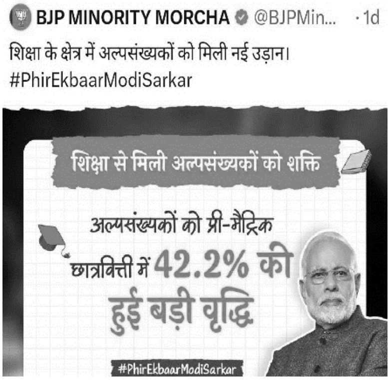
Written by Utkarsh Anand
New Delhi | November 28, 2013 02:17 IST

गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हुए यह दलील पेश किया कि ''सच्चर कमेटी असंवैधानिक थी और इसका मकसद सिर्फ मुसलमानों की मदद करना था।'' गुजरात की मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दिए जाने के 'सच्चर कमेटी' के सुझाव के विरुद्ध दलील देते हुए इसे 'भेदभावपूर्ण' बताया था। गुजरात सरकार का कहना था कि 'सच्चर कमेटी' में मुसलमानों के अलावा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की गई है। मोदी की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ''सच्चर कमेटी न संवैधानिक थी और न कानूनी। इसने सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी जैसे अल्पसंख्यकों की सुध नहीं ली। इसलिए यह किसी योजना का आधार नहीं हो सकती है। कमेटी का मकसद सिर्फ मुसलमानों की मदद करना था।''

दरअसल मोदी की गुजरात सरकार चाहती थी कि प्री-मैट्रिक से पहले मुस्लिमों की दी जाने वाली छात्रवृत्ति की योजना वापस ली जाए। इस पर गुजरात हाईकोर्ट

ने मोदी सरकार के खिलाफ फैसला देते हुए कहा था कि यह योजना पांच धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, न कि केवल मुसलमानों के लिए। हाईकोर्ट के इसी फैसले के विरुद्ध गुजरात की तब की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में गुजरात की तरह ही देश भर में 'सच्चर कमेटी' की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना शामिल हो गया। केवल छह महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुजरात सरकार द्वारा की गई अपील को भूल कर मोदी सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ाती चली गई और 'सच्चर कमेटी' की उन सभी सिफारिशों को मान लिया, जिसे सोनिया गांधी की मनमोहन सरकार ने स्वीकार किया था। इसमें वह प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना भी थी, जिसका विरोध करने के लिए गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोहरे चरित्र का बखान खुद उनकी पार्टी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने यह आंकड़ा जारी कर किया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में 42.2 फीसदी की वृद्धि हुई है।



31 मार्च 2019 को मोदी सरकार ने संसद में सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन की रिपोर्ट पेश की। 27 पेज की इस रिपोर्ट में सरकार ने कहा कि उसने 'सच्चर कमेटी' की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया है और आगे भी यह जारी रहेगा। अर्थात् जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा चुनाव-2014 के प्रचार में 'सच्चर कमेटी' का विरोध करते हुए हिंदुओं से वोट मांग रहे थे, वह प्रधानमंत्री बनते ही केवल पांच साल में मजहब आधारित 'सच्चर कमेटी' की सारी सिफारिशों को लागू कर चुके थे[1]।

यही नहीं, गुजरात में जिस तरह उन्होंने पुलिस थानों में मुस्लिम पुलिसकर्मियों की

[1] सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकारी कार्रवाई तथा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति (31.03.2019 तक की स्थिति)। पूरी लिंक में पढ़ें: https://www.minorityaffairs.gov.in/WriteReadData/RTF1984/2286191517.pdf

भर-भर कर तैनाती की थी, उसी तरह अब वह देश के सभी मुस्लिम इलाके के थाने में मुस्लिम पुलिसकर्मी की बहाली के लिए आदेश जारी कर रहे थे। ज्ञात हो कि यह 'सच्चर कमेटी' के साथ-साथ सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल 'एनएसी' के द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा विधेयक में भी यह सिफारिश शामिल थी। केंद्र की मोदी सरकार ने एक लिखित आदेश में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ''मेरी सभी राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेश की सरकारों से अनुरोध है कि मुस्लिम क्षेत्र के थानों में मुस्लिम पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ मुस्लिम स्वास्थ्य अधिकारी व शिक्षकों की भी नियुक्त करें।'' हिंदू एक बार सोचे कि यदि दंगा हो गया तो मुस्लिम जनता के साथ-साथ उसे मुस्लिम पुलिसकर्मी और मुस्लिम स्वास्थ्यकर्मी की मजहबी भावना का भी सामना करना पड़ेगा! फिर वह कहां से बचेगा? इस विभाजनकारी योजना की जानकारी अल्पसंख्यक मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट- 2019-20 के पेज नंबर-67 पर दर्ज है।



67

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

(vi)	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक तथा थानों में मुस्लिम पुलिस कर्मी की नियुक्ति की अनुशंसा पर विचार करें। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समुचित दिशा–निर्देश जारी करेंगे। इसकी निगरानी के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नोडल विभाग होगा। – कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	कार्यान्वित।
(vii)	शुरू में, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नागरिक अधिकार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ताकि सामाजिक आमेलन की महत्ता को बढावा दिया जा सके। – मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित।
(viii)	अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन

मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम पुलिस की बहाली कार्यान्वित

1.7) वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण

वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 8 लाख 54 हजार 509 संपत्तियां वक्फ के पास है, जो कुल मिलाकर 8 लाख एकड़ से ज्यादा है।

> भारत में सशस्त्र बल और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति यदि किसी के पास है तो वह मुस्लिम आधिपत्य वाला वक्फ बोर्ड है।

देश के वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष के नाते 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक

रूप से मीडिया को यह बताया था कि कांग्रेस की सरकार से अधिक मोदी सरकार ने वक्फ को मजबूत बनाया है और उसकी संपत्ति का डिजिटलीकरण किया है। तत्कालीन मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाद में बताया की डिजिटिज़ेशन का काम पूर्ण हो चूका है।


INDIA TODAY

ews / India / 100 per cent digitisation of Waqf properties completed: Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi

100 per cent digitisation of Waqf properties completed: Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi

Union Minister for Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi said on Friday in a major achievement, 100 per cent digitisation of Waqf properties' records across the count been completed.

Press Trust of India
Kochi, UPDATED: Nov 8, 2019 14:52 IST

13 दिसंबर 2021 को पीआईबी द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, मोदी सरकार ने वक्फ को मजबूत बनाने के लिए 2016-17 में 280 लाख, 2017-18 में 1218 लाख, 2018-19 में 1495 लाख, 2019-20 में 1491 लाख और 2020-21 में 300 लाख का बजट जारी किया।

अपने कार्यकाल के केवल पांच साल में मोदी सरकार ने विभिन्न वक्फ संस्थाओं और बोर्ड को कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने, ऑडिटोरियम, अस्पताल, निकाह केंद्र आदि का निर्माण करने के लिए 1761.90 लाख का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया है। सोच कर देखिए जहां एक ओर सरकार हिंदुओं के मंदिरों पर कर लगाती है और उसके दान का पैसा हड़प लेती है, वहीं मुस्लिमों के वक्फ को ब्याज रहित कर्ज देकर बढ़ावा दिया जा रहा है।

वक्फ संपत्तियों को मजबूती प्रदान करने के लिए मोदी सरकार एक बड़ा सर्वे और ड्राइव का संचालन भी करवा रही है, जिसमें पूरे देश में वक्फ की संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे को कानून की मदद से मुक्त कराई जाएगी। ऐसे 17 हजार संपत्तियों की पहचान की गई है। मई 2017 में वक्फ परिषद के एक सदस्य रईस खान पठान ने एक बयान जारी कर कहा कि, '*मोदी सरकार वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण और विकास को लेकर पूर्व की सरकारों से अधिक गंभीर है। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए यूपीए सरकार के समय जो संशोधित कानून लाया गया था, उसका प्रभावी क्रियान्वयन मोदी सरकार के राज में अब हो रहा है।*

वहीं दूसरी तरफ वक्फ जो हिंदू संपत्तियों पर कब्जा कर रही है, उसके प्रति सरकार उदासीन है। उदाहरण के लिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर के 52 बीघा

जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोंक रखा है, जिस पर अवैध कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद आदि का निर्माण भी कराया जा चुका है। यह केस वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में चल रहा है, जिसकी केस संख्या-45/2022 है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोमनाथ मंदिर के मुख्य ट्रस्टी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन वक्फ के चंगुल से सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन को छुड़ाने के लिए उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।



इसी तरह सूरत की ऐतिहासिक नगरपालिका पर भी वक्फ का अवैध कब्जा है। मणी मंदिर, मोरबी पर अवैध रूप से तीन मंजिला दरगाह बना कर वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं का मंदिर ही हड़प लिया है। हिंदू मंदिरों और संपत्तियों पर ऐसे अनगिनत कब्जे वक्फ द्वारा पूरे देश में किए जा चुके हैं।

1.8) मुस्लिम-ईसाइयों को SC/ST कोटे में आरक्षण का लाभ देने की तैयारी।

धर्मांतरित मुस्लिम व ईसाई को SC/ST कोटा में आरक्षण देने की संभावना तलाशने के लिए मई 2023 में पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में मोदी सरकार ने एक आयोग का गठन। जस्टिस बालाकृष्णन को संघ की पत्रिका आॅर्गेनाइजर क्रिप्टो क्रिश्चिन लिख चुका है और वह सोनिया गांधी के बेहद करीब रह चुके हैं। असल में सोनिया गांधी की मनमोहन सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया था, जिसने 2007 में यह सिफारिश की थी कि धर्मांतरित मुस्लिम और ईसाई को भी SC कोटे में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

मोदी सरकार ने सोनिया गांधी के मनमोहन सरकार की इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए जस्टिस बालाकृष्णन आयोग का गठन किया है। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह के अनुसार, 58 जातियों और 14 जनजातियों में मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जस्टिस बालाकृष्णन आयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय पसमांदा मुसलमानों को SC/ST कोटे में संवैधानिक रूप से आरक्षण देने का रास्ता तलाशने के लिए ही बनाया गया है। इससे हिंदू समाज के दलितों और वनवासियों का हक बड़े पैमाने पर मारा जाएगा और हिंदुओं का तेजी से धर्मांतरण बढ़ेगा।


THE NEW INDIAN EXPRESS

80 per cent Muslims enjoying OBC quota: Ramdas Athawale

By Preetha Nair | Express News Service | Published: 10th October 2022 10:51 AM

मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले के अनुसार, अभी भी OBC कोटा में 80 फीसदी मुस्लिम आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।

ANI को दिए साक्षात्कार में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 70 मुस्लिम जातियों को OBC कोटा का लाभ देते थे।

सरकारी नौकरियों में हिंदी समाज के SC/ST/OBC कोटे का बड़ा लाभ मुस्लिम-ईसाई को देने की तैयारी है। अभी पश्चिम बंगाल के पुलिस भर्ती में OBC कोटा में 100 से अधिक मुस्लिम जातियों ने लाभ उठाया, जिसके कारण हिंदू OBC के बच्चों को सलेक्शन से वंचित रहना पड़ा।

मणिपुर में हिंदू जनजाति मैतेई को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन क्रिश्चियन कूकियों को ST कोटे से आरक्षण का लाभ भी मिलता है और अल्पसंख्यक कोटे का दोहरा लाभ भी मिलता है। हाईकोर्ट द्वारा मैतेई को आरक्षण का लाभ देने की आज्ञा के कारण ही क्रिश्चियन कूकियों ने मैतेइयों का संहार किया और फिर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू न करने का निर्णय लिया।

26 जुलाई 2023 को भारत सरकार ने संसद में एक बिल पेश कर जम्मू-कश्मीर में 'पहाड़ी एथनिक ग्रुप' को ST का दर्जा प्रदान कर दिया। इस पहाड़ी एथनिक ग्रुप में बड़ी संख्या में मुसलिम शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, पूंछ जिले में 90.45 फीसदी, राजौरी में 62.71 फीसदी और कूपवाड़ा व उरी में 100 फीसदी मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं को भ्रमित करने और धोखा देने के लिए जान-बूझ कर 'पहाड़ी एथनिक ग्रुप' लिखा गया, जबकि वास्तव में मुस्लिमों को ST में

शामिल कर उन्हें आरक्षण एवं अन्य सभी लाभ प्रदान कर दिए गये हैं।

1.9) रोहिंग्या/बंग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की योजना?

संसद के अंदर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 'रोहिंग्याओं को इस देश में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं अभी से स्पष्ट कर देता हूं।' लेकिन दूसरी तरफ खूनी रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में आवास देकर बसाया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हरदीप पुरी ने अपने X प्रोफाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए 17 अगस्त 2022 को यह औपचारिक रूप से लिखा कि 'भारत हमेशा से शरणार्थियों का स्वागत करता रहा है। इसी उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट में बसाया जा रहा है। उन्हें 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें यूएनएचसीआर पहचान पत्र और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।' संसद के अंदर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बोला गया झूठ बेनकाब हो गया। गृहमंत्री अपने मंत्री के Post पर बाद में सफाई देने भी आए, परंतु सच यह है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का वह बयान आज भी X पर ज्यों का त्यों उपलब्ध है। उन्होंने उसे नहीं हटाया है। अर्थात् रोहिंग्याओं को बसाने और झूठ बोलकर हिंदुओं को गुमराह करना, सरकार की घोषित पॉलिसी है।


Hardeep Singh Puri (मोदी का परिवार)
@HardeepSPuri

India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision all #Rohingya #Refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs & round-the-clock @DelhiPolice protection.

बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली के मदनपुर खादर कैंप में म्यांनमार से भाग कर आए और रह रहे 1100 रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली के बक्करवाला के 250 फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। सरकार ने इसका भी खंडन नहीं किया।

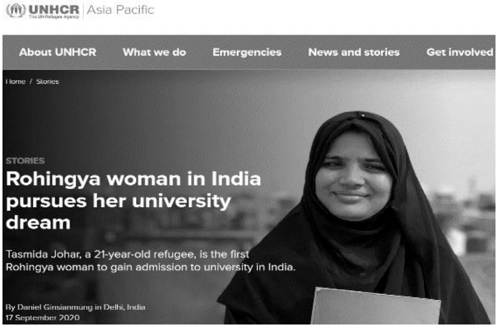
जम्मू-कश्मीर में 40,000 रोहिंग्याओं को इसी सरकार के शासनकाल में बसा दिया

गया। जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रिंकू गिल के 2 मार्च 2020 को मीडिया मंे एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने साफ-सफाई के काम से हिंदू दलितों को हटाकर करीब 400 रोहिंग्याओं को साफ-सफाई के काम में लगाया हुआ है। ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर का शासन अभी केंद्र के ही अधीन है।

उप्र गाजियाबाद के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने 27 जुलाई 2021 को दस्तावेज के साथ एक बड़ा बयान देकर अपनी ही सरकार के मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में गाजियाबाद में 70 फीसदी से अधिक रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किए गये हैं। भाजपा विधायक द्वारा विभाग से मंगवाए गये डाटा से इसका खुलासा हुआ।

UNHCR के अनुसार, भारत ने अपने अंडमान और निकोबार द्विप समूह में 142 रोहिंग्याओं को शरण दी है। इसके लिए UNHCR ने भारतीए एजेंसी और भारत सरकार का धन्यवाद किया।

रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति सरकार के नरम रवैये की एक बानगी संसद में भी देखने को मिली। 28 मार्च 2018 को तत्काली गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में दिए अपने लिखित जवाब में टाल-मटोल के अंदाज में कहा कि 'रोहिंग्या मुसलमानों का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन है।'



यही नहीं, अवैध रोहिंग्याओं को यहां कॉलेज में प्रवेश देकर UN और अरब देशों को खुश करने के लिए इसका ढिंढोरा भी मोदी सरकार पीटने से नहीं चूकती है। उदाहरण के लिए 26 वर्षीय रोहिंग्या लड़की तसमिदा जौहर उर्फ तस्मीन फातिमा म्यानमांर से भागकर बांग्लोदश पहुंची, लेकिन मुस्लिम देश होते हुए भी बांग्लोदश ने उसे शरण नहीं दिया। फिर वह भारत पहुंची। यहां उसे न केवल शरण मिली, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय से उसने स्नातक की पढ़ाई भी

पूरी की, जिसे केंद्र सरकार और उसके मीडिया तंत्र ने उसे भारत की पहली रोहिंग्या ग्रेजुएट के रूप में प्रचारित किया। तस्मीन फातिमा अपने अन्य भाई-बहन व पिता के साथ दिल्ली में रहती है और UNHCR में अनुवादक के रूप में कार्य कर रही है।

रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अगस्त 2017 में राज्यसभा में सरकार ने बताया था कि देश में 40 हजार रोहिंग्याओं के होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार, जम्मू, दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा के नूह, हैदराबाद और उत्तरप्रदेश में रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप हैं। इन 40 हजार में से यूएन की ओर से 21 हजार रोहिंग्याओं को पहचान पत्र जारी किया गया है। वहीं, यह 40 हजार की संख्या भी एक अनुमान ही है। इससे कहीं बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमालन भारत में रह रहे हैं।

चुनाव में नरेंद्र मोदी का भाषण था, "यह बांग्लादेशी अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर तैयार रहें। यह देश इस तरह से नहीं चल सकता।" लेकिन पूर्व गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 29 मार्च 2017 को संसद के अंदर पेश आंकड़े प्रधानमंत्री के झूठ की पोल खोल रहे हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि **बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने में मोदी सरकार की कोई रुचि नहीं है।** संसद में पेश किए गये आंकड़ों के मुताबिक 2014-2017 के दौरान 250 पाकिस्तानी और 1750 बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा गया है।

19 जुलाई 2017 को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में देश के गृहमंत्री ने घुसपैठ पर पूछे गये सवाल का जवाब टाल-मटोल के अंदाज में देते हुए कहा कि 'बंग्लादेशियों का प्रवेश चोरी-छिपे होता है, इसलिए ऐसे मामलों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।' सवाल उठता है कि फिर चुनावी भाषण में आम जनता



से नरेंद्र मोदी झूठ क्यों बोलते हैं कि घुसपैठियों को निकाल देंगे, जबकि सत्ता में आने पर कहते हैं कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है?

जिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गूंगा और रोबोट कहा जाता था, उनकी सरकार के दौरान अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने को रिकॉर्ड मोदी सरकार से कहीं बेहतर है। गृहमंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2005-2013 के बीच 88,792 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला गया था, वहीं 2014-2019 के बीच मात्र 2,566 बांग्लादेशियों को ही देश से बाहर निकाला जा सका है।

1.10) कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार से मोदी सरकार ने किया किनारा

26 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 बिल पेश किया। इस बिल के पैरा-2 में सरकार ने लिखा कि कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार नहीं, बल्कि हिंदुओं का पलायन हुआ था। सरकार ने इस बिल के जरिए कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार से पल्ला झाड़ कर मुस्लिम जिहादियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बचाने का कार्य किया है।

भगवान शिव, शारदा, ऋषि काश्यप और शंकराचार्य की भूमि जम्मू-कश्मीर में स्प्रिचुअल टूरिज्म के नाम पर सूफी सर्किट का विकास किया जा रहा है।

1.11 भाजपा शासित कुछ राज्यों का अल्पसंख्यक तुष्टिकरण भी देख लीजिए

हिंदू हितों का दिखावा करने वाली उप्र की योगी सरकार भी पीछे नहीं है। वह तो अंतरजाति के अलावा अंतर-धार्मिक शादी अर्थात् हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाह कराने के लिए अलग से बजट जारी करती है और हर विवाहित जोड़े को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। यह योजना 'लव जिहाद' को भी बढ़ावा दे रही है, जिसकी शिकार अधिकांशतः हिंदू समाज की लड़कियां ही हो रही हैं।

उप्र प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधानसभा में खुलकर यह

घोषणा की कि पूर्व की अखिलेश यादव की सरकार से अधिक उन्होंने अल्पसंख्यक कार्यक्रम चलाए और उसके लिए अधिक बजट खर्च किए हैं और यह बात आंकड़ों से भी जाहिर होता है। 2012-2017 के बीच सपा की अखिलेश सरकार ने अल्पसंख्यकों पर जहां 3,50,862 करोड़ रुपये खर्च किया, वहीं 2017 से दिसंबर 2021 तक में ही योगी सरकार ने अल्पसंख्यों पर 4,19,264 करोड़ रुपये खर्च किया था। सपा सरकार की योगी सरकार द्वारा खर्च की गई यह रकम 68,402 करोड़ रुपये अधिक है। उप्र की योगी सरकार ने भी केंद्र की मोदी सरकार ही तरह 30-35 फीसदी सरकारी संसाधनों पर अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को अधिकार दे दिया है।

2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 2018-19 में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2757 करोड़ रुपये का बजट जारी किया। अगले वर्ष 2019 में चुनाव था, इसलिए हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए उन्होंने 2019-20 के अल्पसंख्यक बजट में कटौती का दिखावा करते हुए 1401 करोड़ रुपये का बजट जारी किया और मीडिया में यह प्रचारित किया कि योगी ने अल्पसंख्यों के बजट में 50 फीसदी की कटौती कर दी है! योगी सरकार का यह पैटर्न आगे भी बना रहा। चुनावी साल 2024 के बजट में अल्पसंख्यों की छात्रवृत्ति के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया हैं और इसे भी बजट में कटौती के तौर पर प्रचारित कर हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम किया गया है, जबकि इससे पहले 2022-2023 के बजट में केवल प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक बजट पर ही करीब 795 करोड़ रुपये खर्च किया गया था।

योगी सरकार ने की मदरसों पर कार्रवाई की खबर मीडिया में खूब प्रचारित की गई, लेकिन यदि 2022-23 के बजट को देखें तो अरबी-फारसी पढ़ाने वाले मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर 479.07 करोड़ रुपये खर्च किया गया।

उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने तो अल्पसंख्यकों के लिए बढ़े बजट को आधार बना कर 29 जून 2023 को अपने X हैंडल पर यह घोषणा ही कर डाली, 'पसमांदा मुसलमानों जागो, सपा-बसपा-कांग्रेस को छोड़ो, भाजपा से नाता जोड़ो।'

उप्र भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने 15 जनवरी 2024 को एक बयान दिया, जो दैनिक जागरण में छपा। उनके बयान के मुताबिक,

"मोदी सरकार ने हज का कोटा 65 हजार से बढ़ाकर 1.75 लाख किया और हज के लिए औरत साथ पुरुष के भी जाने की बाध्यता को खत्म किया। उन्होंने कहा कि उप्र में 50 लाख में से 20 लाख मकान मुस्लिम महिलाओं को मिले हैं।"

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिमों को खुश करने के लिए एनकाउंटर में मारे गये अपराधियों की धार्मिक पहचान उप्र की योगी सरकार ने जारी की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा जारी डाटा के अनुसार, "उप्र में 2017-2023 तक 183 अपराधियों का एनकाउंटर उप्र पुलिस ने किया था। इसमें 5046 अपराधी जख्मी हुए थे जबकि 13 पुलिसकर्मियों का बलिदान हुआ और 1443 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।"

भाजपा क अल्पसंख्यक मोर्चा साफ-साफ लिखता है कि "कुल मारे गये 183 अभियुक्तों में से मुसलमान केवल 59 थे, जो मारे गये कुल अभियुक्तों में केवल 32.24 प्रतिशत होते हैं।" बांकी के 67.6 फीसदी अभियुक्त हिंदू एवं अन्य धार्मिक समुदाय से थे। अर्थात् 183 में 124 हिंदू एवं अन्य धर्म के अभियुक्तों का एनकाउंटर उप्र की योगी सरकार की पुलिस ने किया था।

2023 में उप्र में अल्पसंख्यकों को 7000 करोड़ से ज्यादा का ऋण बैंकों ने आवंटित किया।

उप्र मदरसा बोर्ड के छात्रों लिए केंद्र की सरकारी नौकरियों और सेना में भर्ती का रास्ता खोला जा रहा है। इसके लिए यूपी मदरसा बोर्ड भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल में पंजीकरण कराने जा रहा है।

इसी तरह भाजपा महाराष्ट्र सरकार ने भी अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की रकम को दोगुना करने का काम किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के छात्रवृत्ति की रकम 2011 में कांग्रेस की सरकार ने 25000 रुपये प्रति छात्र तय किया था, जिसे शिंदे की भाजपा सरकार ने अब 50,000 रुपये प्रति छात्र कर दिया है।

भाजपा की शिंदे सरकार ने 2022-23 में महाराष्ट्र के सभी मदरसों को 10 लाख रुपये आवंटित करने की घोषणा की।

महराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मौलाना आजाद माइनोरिटीज फिनांशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन का बजट 30 करोड़ से बढ़ा कर 500 करोड़ करने की घोषणा की।

भाजपा शासित मप्र में भी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 36 फीसदी लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं हैं। मप्र में प्रति माह 1000 रुपये पानी वाली 1.25 करोड़ महिलाओं में 45 लाख महिलाएं मुस्लिम हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिमों की आबादी मात्र 6.6 फीसदी है। अर्थात् आबादी के अनुपात में छह गुणा लाभ दिया जा रहा है।

असम की भाजपा की हिमंता बिस्वसरमा की सरकार हिंदुओं को धोखा देने में दो कदम और आगे निकल गई। हिमंता सरकार ने हिंदुओं को धोखा देते हुए इमारत से मदरसा शब्द हटाकर स्कूल लिख दिया और मीडिया में यह प्रचारित कर दिया कि उसने मदरसों को बंद कर दिया है जबकि उसमें बच्चे, मौलवी और पढ़ाई- सब पूर्ववत जारी है। दैनिक भास्कर की 3 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हिमंता बिस्वसरका ने असम के मदरसांे को अलकायदा का दफ्तर बताते हुए इसे बंद करने एक ऐलान किया था, लेकिन आप हैरान होंगे कि वह अभी भी चल रहा है, बस बिल्डिंग से मरदसा हटाकर उस पर स्कूल लिख दिया गया है!

हरियाणा जैसे हिंदू बहुल राज्य में 12,505 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कर दिया गया है। वहां के गांवों में वक्फ की संपत्तियों में वृद्धि की जा रही है। 8190 वक्फ संपत्ति हरियाणा के हिंदू बहुल गांव में खड़ी हो गई है। वहां 4272 मस्जिदें बनकर तैयार हो गई। वहां 300 से अधिक इमामों को सैलरी और पेंशन की सुविधा दी जा रही है। इमामों की सैलरी को जनवरी 2023 में 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है।

1.12) मुस्लिमों तुष्टिकरण से खुश अरब देशों ने किया पीएम मोदी को सम्मानित?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक 14 देशों ने सम्मानित किया है, जिसमें सात मुस्लिम देश शामिल हैं। उन्हें पुरस्कृत करने वाले मुस्लिम देशों में सउदी अरब, मिश्र, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमिरात और बहरीन शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, न्यू पापुआ गिनी, फिजी, पलाउ

गणराज्य, भूटान और रूस ने भी उन्हें पुरस्कृत किया है।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अपने सोशल प्लेटफार्म से बार-बार प्रधानमंत्री को केवल मुस्लिम देशों द्वारा सम्मानित किए जाने को ही प्रचारित करता है। वह शायद भारत के मुस्लिमों को खुश करने के लिए यह संदेश देना चाहता है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम तृष्टिकरण के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, इसलिए मुस्लिम देश उन्हें सम्मानित कर रहे हैं।



सन्दर्भ: नीचे दिए गए सभी संदर्भ मोदी सरकार तथा उनके ही नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। इस पुस्तक में ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जो लेफ्ट लॉबी या मोदी विरोधियों द्वारा प्रकाशित किया हो। सभी डाटा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और सरकार के द्वारा ही साझा किया गया है।

(c) & (d): The Central Universities are autonomous institutions created under the Act of Parliament which are governed by their own Acts, Statutes, Ordinances etc. and Regulations made thereunder and are competent to take decision in academic and administrative matter of the University including increasing of fees (Tuition, hostel and mess fee etc.).

(e) & (f): The details of fund allocation/released to the universities i.e. Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Jamia Millia Islamia, New Delhi; Aligarh Muslim University; Rajiv Gandhi University, Itanagar; Banaras Hindu University since 2014 is as under:-

(Rs. in Crores)

Name of the Central University	Funds Allocated/Released								
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (upto 30.06.2022)
JamiaMilliaIslamia	264.48	293.26	305.87	333.20	362.99	361.91	479.83	411.10	105.95
Jawaharlal Nehru Univ.	336.91	301.31	332.46	373.51	371.65	416.57	373.52	407.47	124.71
Aligarh Muslim University	673.98	825.04	894.70	1106.02	1009.69	1180.00	1520.10	1214.63	302.32
Banaras Hindu University	669.51	749.28	892.47	1116.35	1084.42	1271.13	1137.16	1303.01	325.29
Rajiv Gandhi University	39.93	69.94	77.38	79.11	61.75	101.27	97.14	102.79	45.32

AMU को दिया गया सालाना फण्ड



Some girls & boys out of the 19 ZFI Fellows joining the Civil Services in 2019

जकात फाउंडेशन के IAS





बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा साझा किया गया सरकारी डाटा।

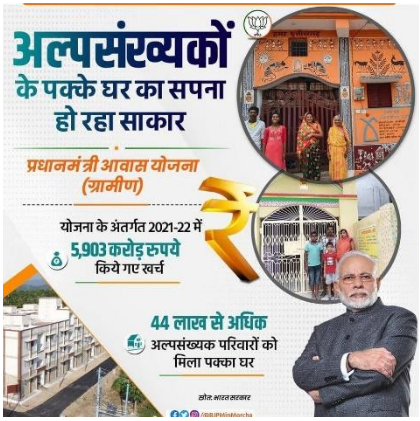












BJP MINORITY MO... · 5d

क्या यूपी में हो रही कार्यवाही एक धर्म विशेष के ख़िलाफ़ है? एक ... आकड़ों पर।

183 अभियुक्त मारे गए, 13 पुलिसकर्मी शहीद
5046 जख्मी हुए, 1443 पुलिसकर्मी ज़ख्मी
कुल 183 ढेर हुए अभियुक्तों में 59 मुसलमान
मारे गए कुल अभियुक्तों में 32.24% मुसलमा

2023
14 मारे गए- 5 मुसलमान
2022
14 मारे गए, 1 मुसलमान
2021
26 मारे गए, 7 मुसलमान
2020
26 मारे गए, 5 मुसलमान
2019
34 मारे गए, 12 मुसलमान
2018
41 मारे गए, 14 मुसलमान
2017
28 मारे गए, 15 मुसलमान
सबसे बड़े इनामी 5-5 लाख वाले असद-गुला
2.50 लाख के इनामी जो ढेर हुए
आदित्य राना, बिजनौर
शकील, संभल

BJP MINORITY MO... · 4d



BJP MINORITY... · 14 Apr

आधुनिकीकरण, तकनीकी शिक्षा से अल्पसंख्यक युवाओं के हौसले बढ़ा रही भाजपा सरकार।

नई मंजिल योजना के अंतर्गत 99,980 अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

#AmritMahotsav



Amit Malviya @amitmalviya

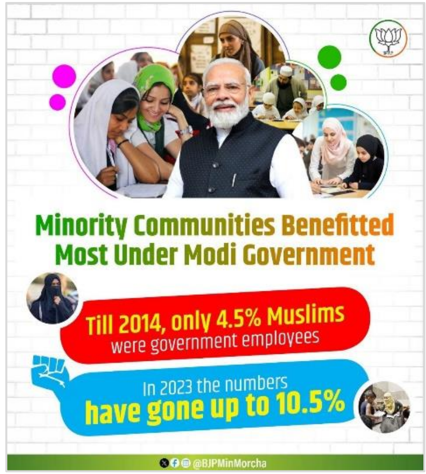
FM demolishes West's 'perception' of Muslim persecution...

Minorities
Before 2014
20,000 skill trained
5% with Govt jobs
3cr scholarships
70% girl school dropout rate

After 2014
2Mn skill trained
10% with Govt jobs
5cr scholarships
Free UPSE coaching

हिन्दुओं से धोखा और भारत से द्रोह !

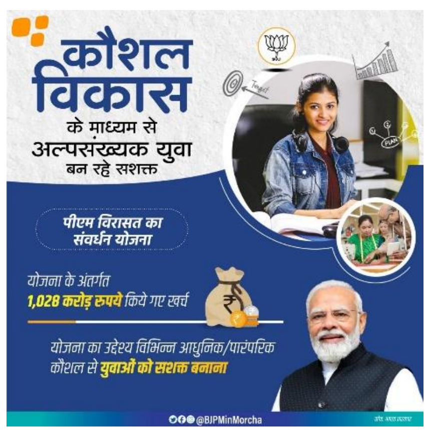






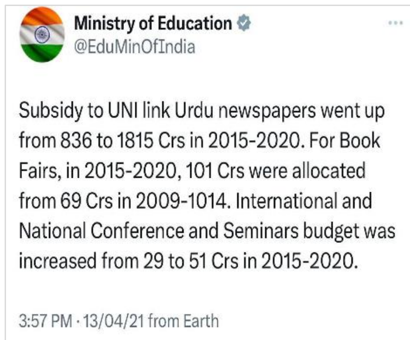







BJP MINORITY... · 06 Apr
OUR LEADER — OUR PRIDE
Six Muslim countries decorated @narendramodi ji with their highest honours.
1. Saudi Arabia
2. Afghanistan
3. State of Palestine
4. Maldives
5. UAE
6. Bahrain


अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा में अब गरीबी नहीं बनेगी बाधा
नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS)
योजना के तहत
प्रति माह 500 रुपये
की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को
पढ़ाई छोड़ने से रोकना
योजना का मुख्य उद्देश्य
/@BJPMinMorcha


Ministry of Education
@EduMinOfIndia
Subsidy to UNI link Urdu newspapers went up from 836 to 1815 Crs in 2015-2020. For Book Fairs, in 2015-2020, 101 Crs were allocated from 69 Crs in 2009-1014. International and National Conference and Seminars budget was increased from 29 to 51 Crs in 2015-2020.
3:57 PM · 13/04/21 from Earth


आम जिंदगी
चुनावी जिंदगी
ऑपइंडिया
@OpIndia_in
कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी जुलूस पर पत्थर बरसाए, दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए श्रद्धालु: लखनऊ में हिन्दू संगठनों ने दिया थाने पर धरना
#RamNavami #Lucknow
Translate Tweet
hindi.opindia.com
कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी जुलूस पर पत्थर बरसाए, दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए श्रद्धालु
22:13 · 30 Mar 23 · 39.4K Views
BJP
@BJP4India
मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, मोदी सरकार की प्राथमिकता...
#Sabki_Sarkar
तीन तलाक
की कुप्रथा पर वार
मुस्लिम महिलाओं को मिला समान अधिकार
7,760 views
9:15 · 04 Apr 23 · 27.4K Views
449 Retweets 24 Quotes 962 Likes


BJP MINORITY MO... · 4d

अल्पसंख्यक युवाओं के विकास के लिए समर्पित भाजपा सरकार।

सीखो और कमाओ योजना से अल्पसंख्यक युवाओं का बढ़ रहा कौशल।

#AmritMahotsav

2 41 58 1,3


BJP MINORITY MO... · 2d

हज यात्रा को सुविधाजनक बना रही मोदी सरकार।

- हज पॉलिसी 2023 में यात्रा आवेदन हुआ नि:शुल्क।
- 45 वर्ष से अधिक की महिलाएं अकेले हज यात्रा के लिए कर सकती हैं आवेदन।
- वीआईपी कोटे की कुल 500 सीटों को किया खत्म।

#NewIndia #AmritMahotsav


BJP MINORITY MOR... · 1d

अल्पसंख्यकों के हुनर को देश-विदेश में पहचान दिला रही @narendramodi सरकार।
उस्ताद योजना के माध्यम से कला एवं शिल्प से जुड़े लोगों का निखर रहा हुनर, योजना के अंतर्गत 167 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।

#NewIndia #AmritMahotsav

3 38 67 1,411


BJP MINORITY MOR... · 1d

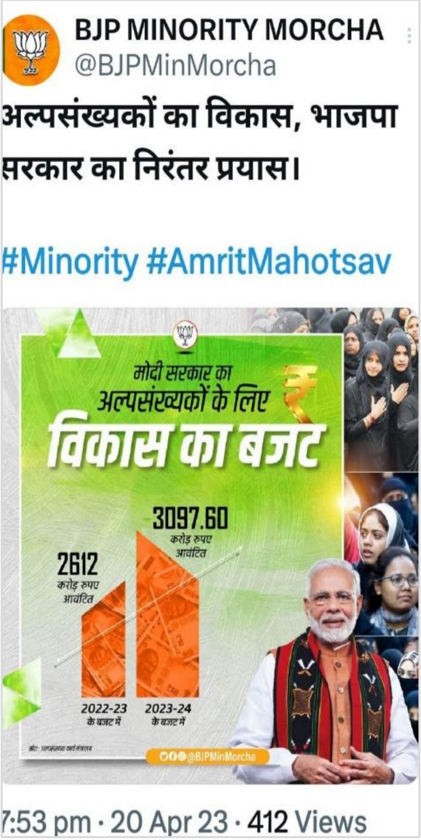
मोदी सरकार की नया सवेरा योजना से संवर रहा अल्पसंख्यक छात्रों का भविष्य।

#NewIndia #AmritMahotsav

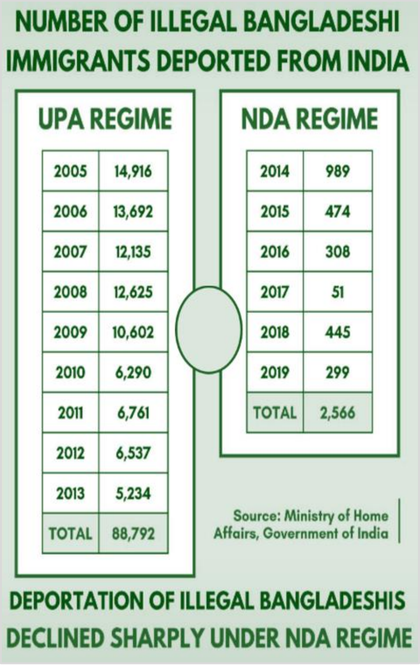
3 24 41 474

हिन्दुओं से धोखा और भारत से द्रोह !









UPA REGIME

2005	14,916
2006	13,692
2007	12,135
2008	12,625
2009	10,602
2010	6,290
2011	6,761
2012	6,537
2013	5,234
TOTAL	88,792

NDA REGIME

2014	989
2015	474
2016	308
2017	51
2018	445
2019	299
TOTAL	2,566

अगले अध्याय में,

"मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को बनाया संस्थागत"



जल्द आएगी पूरी पुस्तक